RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार, 05 नवंबर 2022 वर्ष 04 अंक 172 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

मुंबई दंगों के पीड़ितों का पता लगाकर मुआवजा दे महाराष्ट्र सरकार

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1992-93 के मुंबई दंगों के सभी पीड़ितों का पता लगाने का निर्देश दिया, जिससे कि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करने में विफल रही थी। शीर्ष अदालत ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भारत के संविधान के अनुच्छेद- 21 के तहत प्रदत लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफलता थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, अगर नागरिकों को सांप्रदायिक तनाव के माहौल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अनुच्छेद- 21 द्वारा मिले जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। दिसंबर, 1992 और जनवरी, 1993 में मुंबई में हुई हिंसा ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। दंगे में 900 व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकों के घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और संपत्ति नष्ट हो गई। ये सभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले उनके अधिकारों का उल्लंघन है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार से मुआवजे की मांग करने का अधिकार है क्योंकि उनकी पीड़ा का एक मूल कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की विफलता थी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 108 लापता व्यक्तियों के कानूनी वारिसों का पता लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करें, जिससे कि जनवरी 1999 से उन्हें 9 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जा सके। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फरार आरोपियों का पता लगाने के लिए निष्क्रिय मामलों को फिर से शुरू करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर निष्क्रिय 97 मामलों का विवरण बंबई हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदान करने के लिए भी कहा है।

पीएम मोदी ने शिंदे सरकार की छवि

के लिए किया महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स का ऐलान, बोले कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले

महाराष्ट्र : कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गुजरात के विकास के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कई विकास परियोजनाओं के पड़ोसी राज्य गुजरात चले जाने का हवाला दिया।मीडिया से बातचीत करते हुए पटोले ने आरोप लगया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार की छवि को बचाने के लिए महाराष्ट्र के लिए योजनाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के लिए दो लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया।

पीएम मोदी ने यह ऐलान कल मुंबई में आयोजित किए गए रोजगार मेला को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने 2 लाख करोड़ के 225 छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। यह ऐलान तब हुआ जब पिछले पांच बड़े प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में आने वाले थे और अन्य राज्यों में चले गए, जिनमें तीन तो सिर्फ गुजरात शिफ्ट हुए। इसके बाद विपक्ष लगातार शिंदे फडणवीस सरकार पर आक्रामक होता रहा है और शिंदे-फडणवीस सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि शिंदे गुजरात का काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पटोले ने विपक्ष के अन्य नेताओं की तरह मुख्यमंत्री को आड़े लेते हुए यही दोहराया कि राज्य सरकार गुजरात के विकास के लिए काम कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र आने वाली सभी बड़ी परियोजनाएं पड़ोसी राज्य गुजरात स्थानांतरित हो रही हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिंदे-फडणवीस सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की वजह से बनी क्योंकि जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ व विरोधी नेताओं को भयभीत करने के लिए किया गया।

महाराष्ट्र से गुजरात बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जाने पर बोले नाना पटोले

पटोले का भी यह बयान ऐसे समय में ही आया है जब महाराष्ट्र में प्रस्तावित कुछ बड़ी परियोजनाओं के गुजरात और अन्य राज्यों में जाने के बाद शिंदे सरकार विपक्ष के हमले का सामना कर रही है।विपक्ष शिंदे-फडणवीस सरकार को वेदांता-फॉक्सकॉन और टाटा-एयरबस परियोजना के गुजरात चले जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है।

मुंबई के अस्पताल में मिली 132 साल पुरानी सुरंग

मुंबई : मुंबई स्थित सरकारी जेजे अस्पताल में 132 साल पुरानी सुरंग मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश राज में बनी इस 200 मीटर लंबी सुरंग की आधारशिला पर 1890 की तिथि अंकित है। अधिकारी ने संवाददाताओं से बताया कि जिस भवन के नीचे यह सुरंग मिली है पहले उसका उपयोग महिलाओं और बच्चों के उपचार के लिए वार्ड के रूप में होता था। अस्पताल परिसर में स्थित इस भवन को बाद में नर्सिंग कॉलेज में बदल दिया गया। अधिकारी ने बताया, ''पानी लीक होने की शिकायत के बाद हमने नर्सिंग कॉलेज भवन का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और सुरक्षा गार्ड ने भवन को सर्वे किया और पाया कि उसकी आधारशिला पर 1890 की तारीख है।'' उन्होंने कहा, ''कुछ कर्मचारियों ने हमें कहा कि वहां सभवतः भूतल हो सकता है, जिसके बाद हमने और निगरानी की और सुरंग का पता चला।''

हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमले की धमकी

मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया कॉल

मुंबई : मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को कॉल पर मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है. इस कॉल के बाद ताड़देव पुलिस मौके पर पहुंची और हाजी अली दरगाह को अलर्ट कर दिया गया है. मौके पर एक बीडीडीएस और कॉन्वेंट वेन को भी रवाना किया गया. इस दौरान इलाके में एल एंड टी के प्रोजेक्ट साइट की जांच की गई. हालांकि, अभी तक टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जब कॉलर को दोबारा कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था. कॉलर कौन था और कॉल के पीछे का कारण क्या था इसे लेकर भी जांच की जा रही है. अभी तक यह पता लग पाया है कि कॉल करने वाला व्यक्ति उल्हासनगर का है और वह दिमागी रूप से बीमार है. उसका इलाज भी चल रहा है. यह फोन बीते दिन 3 नवंबर को किया गया था.

अगस्त में भी मिली थी धमकी

इससे पहले 20 अगस्त को भी मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आतंकी हमले की चेतावनी मिली थी. मुंबई के सीपी विवेक फनसालकर ने बताया था कि देर रात मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को कुछ मैसेज मिले थे, जिसमें आतंक फैलाने की बात करते हुए धमकी दी जा रही थी.

26/11 जैसे हमले की दी थी धमकी

इन संदेशों में पिछले उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए भारत में 26/11 के हमले जैसी घटना दोहराने की बात कही गई थी. संदेश में लिखा है कि यह नंबर ट्रेस करोगे तो यह बाहर का निकलेगा लेकिन, मुंबई में धमाका करने वाले लोग जल्द पहुंचने वाले हैं.

संपादकीय / लेख

फिर प्रदूषण की मार...!

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है। अस्वस्थ लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी है। एक अनुमान के मुताबिक, प्रदूषण में पराली की मात्रा 30 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। भय यह है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण ज्यादा बढेगा। पिछले साल दिसंबर के आखिर में प्रदूषण चरम पर पहुंच गया था और इस साल अभी नवंबर की शुरूआत हुई है। अगर प्रदूषण रोकने के उपाय न किए गए, तो इस साल यह शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के आंकडे.अब डरा नहीं रहे हैं। प्रदूषण को लेकर आम लोग कितने चिंतित हैं, इसका अनुमान मोटे तौर पर हम दीपावली के समय हुई आतिशबाजी से लगा सकते हैं। प्रतिबंधों और दिशा-निदेशों को मानने को हम तैयार नहीं हैं, नतीजा सामने है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बता दिया कि पंजाब में पराली जलाने की घटना में 2021 की तुलना में 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यह भी बता दिया कि हरियाणा (जहां भाजपा सत्ता में है) में पराली जलाने में 30.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह आरोप गंभीर है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिल्ली को गैस चैंबर में बदलने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल, पंजाब सरकार किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये नकद प्रोत्साहन देना चाहती थी, ताकि किसान पराली न जलाएं और दूसरे प्रकृति अनुकूल उपाय आजमाएं। इस योजना में केंद्र सरकार से भी पैसा देने के लिए कहा गया, पर केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, नतीजा यह कि पंजाब के किसान इस बार कुछ ज्यादा ही पराली जला रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां यह बोल जरूर रही हैं कि पर्यावरण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर किसी की चुप्पी हो या आरोप, सबके पीछे राजनीति ही है। प्रदूषण घटाने के लंबे-चौड़े वादे करने वाले अपने-अपने सियासी झुकाव के हिसाब से आचरण कर रहे हैं। पराली जलाने की कुप्रथा के अंत के लिए किसी आंदोलन की जरूरत क्या किसी को महसूस नहीं हो रही?

यह सही है किसानों के खिलाफ कडे.कदम समाधान नहीं हैं। उन्हें जल्दी गेहूं बोने के लिए खेत तैयार करने हैं, उन्हें क्या कहा जाए? हालांकि, जिस दिल्ली तक पंजाब के किसान प्रदूषण पहुंचा रहे हैं, उस दिल्ली में क्या उनका कोई परिजन, मित्र नहीं रहता है? कोई भी देश कानून या कड़ाई से नहीं बनता, अपने लोगों के निहित स्वार्थों से नहीं बनता। देश तब बनना शुरू होता है, जब लोग एक-दूसरे के हित में सोचना शुरू करते हैं। बेशक, पराली जलाने की कुप्रथा से देश बिगड़ रहा है, लोगों को सोचना चाहिए, तभी शायद सरकारें भी सोचना शुरू करेंगी। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और भूमि को जो स्थायी नुकसान हो रहा है, उस पर समग्रता में सोचना पड़ेगा।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

ओमायक्रॉन के सब वैरिएंट 'एक्सबीबी' से संक्रमित...!

मुंबई : मुंबईकरों पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इस बार ओमायक्रॉन के सब वैरिएंट 'एक्सबीबी' से काफी लोग संक्रमित हुए हैं। मनपा द्वारा जारी १६वें जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई में रहनेवाले २३४ संक्रमितों के नमूनों की जांच की गई। इनमें शत-प्रतिशत मरीज ओमायक्रॉन से संक्रमित मिले। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे चिंता की बात यह है कि इसमें ओमायक्रॉन के सब वैरिएंट 'एक्सबीबी' से १५ फीसदी, जबकि 'एक्सबीबी.१' से १४ फीसदी मरीज संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि कोविड वायरस के नए सब वैरिएंट्स का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग अगस्त २०२१ से ही किया जा रहा है। इसके जरिए वायरस के कई वैरिएंट्स की पहचान की जाती है। उसके अनुसार उपचार की सही दिशा निर्धारित करना आसान हो जाता है। नतीजतन रोगियों का इलाज करना भी संभव है।

कुल २३४ नमूनों में से सभी में ओमायक्रॉन वैरिएंट मिला है। इसके अलावा १५ फीसदी अर्थात ३६ लोग ओमायक्रॉन के सब वैरिएंट एक्सबीबी और १४ फीसदी यानी ३३ लोग एक्सबीबी.१ से संक्रमित मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रमितों में शून्य से २० साल के २४, २१ से ४० साल के ९४, ४१ से ६० साल के ६९, ६१ से ८० साल के ३६ और ८१ से १०० साल के ११ मरीज शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि २३४ संक्रमितों में से ८७ लोगों ने कोविड रोधी टीके की एक भी खुराक नहीं लगवाई। इनमें से १५ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि एक भी मरीज को आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी।

४० हजार कंपनियों पर 'लॉक' लगाने की तैयारी

मुंबई : मोदी सरकार ४० हजार कंपनियों पर 'लॉक' लगाने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन वैंठसिल किया जाएगा, जिससे ये व्यवसाय नहीं कर पाएंगी। हालांकि इनमें कई कंपनियों का कामकाज धीमा है तो कुछ कंपनियों को फेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में ये लिस्ट तैयार की है। इसके तहत कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ४० हजार से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन वैंठसिल करने की योजना बनाई है। इसमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट मंत्रालय ऐसी कंपनियों पर ताला लगाने की तैयारी कर रहा है, जिनका कारोबार छह महीने से निष्क्रिय रहा है। सरकार का कहना है कि ऐसी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अंदेशा है।

बिपाशा बसु ने कराया बोल्ड अंदाज में मैटरनिटी फोटोशूट, यूजर्स बोले- अश्लीलता की हद...

अभिनेत्री बिपाशा बसु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियोज साझा करती रहती हैं, जिन पर फैंस प्यार भी लुटाते नजर आते हैं। अब बिपाशा ने मैटरनिटी फोटोशूट कराया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा की है। हालांकि इस बार अपने इस फोटोशूट की वजह से वह काफी ट्रोल हो रही हैं। कुछ यूजर्स को उनका बोल्ड अंदाज में मैटरनिटी फोटोशूट करवाना रास नहीं आया और बिपाशा की तस्वीर वायरल होते ही लोग एक के बाद एक प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं।

मैटरनिटी फोटोशूट में बिपाशा बसु ने गोल्डन कलर के कपड़े से खुद को कवर किया हुआ है और उन्हें स्टूल पर बैठकर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है। एक्ट्रेस के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बिपाशा ने कैप्शन में लिखा- ह्लहर समय खुद से प्यार करें, जिस शरीर में आप रहते हैं उससे प्यार करेंह्व। उनकी इस तस्वीर को पैपराजी पेज वायरल भयानी से भी री-शेयर किया गया है और तस्वीर वायरल होते ही ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

बिपाशा बसु की मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा- ह्लकम से कम प्रेग्नेंसी में तो ऐसी तस्वीरें खिंचवाना जरूरी नहीं हैह्व। वहीं दूसरे ने लिखा- अश्लीलता की हद हो गई। इसी तरह से अन्य भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कई यूजर्स बिपाशा की तुलना पॉप सिंगर रिहाना से भी करते नजर आए। हालांकि उनके फैंस अभिनेत्री से खुशखबरी के बारे में भी सवाल करते दिखाई दिए।

खुद से आधी उम्र की अंकिता से शादी कर चर्चा में आए थे मिलिंद

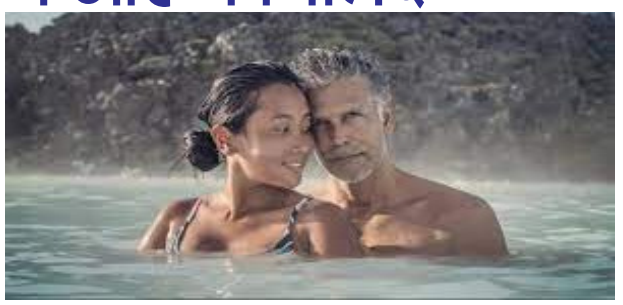

फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले मिलिंद सोमन बॉलीवुड, टेलीविजन और मॉडलिंग जगत तीनों ही जगह अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। बतौर मॉडल अपने करियर की शुरूआत करने वाले मिलिंद सोमन आज भी जब रैंप पर उतरते हैं, तो यंग मॉडल उनके आगे फीके नजर आते हैं। मिलिंद ने खुद से 26 साल छोटी लड़की अंकिता कोंवर से शादी कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। 4 नवंबर 1965 को जन्मे मिलिंद सोमन आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं।

मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर की पहली मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी। इस दौरान दोनों एक-दूसरे को देख कर अनदेखा नहीं कर पा रहे थे और बार-बार नजरें टकरा रही थीं। ऐसे में हिम्मत जुटाकर अंकिता ने मिलिंद को डांस के लिए पूछा और उन्होंने हां कर दी। इसके बाद दोनों ने डांस किया और अंकिता ने मिलिंद से उनका नंबर मांगा लिया। कुछ दिनों तक दोनों ने फोन पर बात की और अच्छे दोस्त बन गए।

मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती जा रही थी और इसी बीच अंतिका पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अंकिता के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई, जिसने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। इस दर्द से उभरने में मिलिंद सोमन ने अंकिता का काफी साथ दिया। धीरे-धीरे दोनों की मुलाकातों की सिलसिला बढ़ा और उनकी दोस्ती गहरी होने लगी।

सरकार बदलने के बाद भी नासिक वासियों को संपत्ति कर में राहत नहीं

नासिक : बीजेपी के सत्ताकाल में नासिक वासियों पर अधिक संपत्ति टैक्स लगाया गया था। सत्तांतर होने के बाद इस टैक्स बढ़ोतरी से नागरिकों को राहत मिलने की आस थी, लेकिन महा विकास आघाड़ी सरकार और अब बीजेपी और शिवसेना (बालासाहब ठाकरे) की सरकार ने भी नासिक वासियों को टैक्स बढ़ोतरी से राहत नहीं दी। निवासी क्षेत्र में की गई दो गुणा संपत्ति टैक्स कायम रखा गया है। अनिवासी अर्थात व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति टैक्स में हुई 4 गुणा बढ़ोतरी कम करने का आश्वासन पालक मंत्री भुसे ने दिया। दूसरी ओर नासिक के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किए गए निओ मेट्रो प्रकल्प को एक महीने में मंजूर मिल सकती है। यह जानकारी महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने दी। दरमियान नोकर भरती, भूसंपादन, जलापूर्ति निधि को लेकर जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन भुसे ने दिया। पालक मंत्री दादा भुसे की मौजूदगी में महानगरपालिका में जायजा बैठक का आयोजन किया गया था। इस समय सांसद हेमंत गोडसे, बीजेपी विधायक देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले, महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. पुलकुंडवार, उपायुक्त मनोज घोडे पाटिल, नगर रचना विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस समय सिंहस्थ कुंभमेला की दृष्टि से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। बीजेपी के सत्ता काल में संपत्ति टैक्स बढ़ाया गया था। निवासी क्षेत्र में दो गुणा तो अनिवासी क्षेत्र में चार गुणा बढ़ोतरी की गई

है। निवासी उपयोग का संपत्ति टैक्स मिल रहा है, लेकिन अनिवासी संपत्ति टैक्स न मिलने से यह दर बढ़ोतरी कम करने की सूचना की गई। इस बारे में जल्द ही निर्णय लेने की बात भुसे ने की। निओ मेट्रो प्रकल्प यह केंद्र सरकार के पास अंतिम चरण में है, जिसे एक महीने में मंजूरी मिलेगी। अमृत 2 योजना से 350 करोड़ रुपए का जलापूर्ति प्रस्ताव और 400 करोड़ रुपए का मलनिस्सारण प्रस्ताव को निधि मिलने वाला है। आज की स्थिति में इलेक्ट्रिक बस खरीदी के लिए निधि मिलने हेतु केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है नमामी गोदावरी इस प्रकल्प के सलाहकार की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद डीपीआर तैयार किया जाएगा। दमकल विभाग के 458 पद पर भर्ती की जा रही है। शेष पद के लिए जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। यह आश्वासन भुसे ने दिया।

होटल मिर्ची के पास उड्डाण पुल बनाने की मांग

होटल मिर्ची के पास हुई भीषण दुर्घटना के बाद ट्रैवल बस के लिए कन्नमवार पुल के नीचे नदी पात्र के पास वाहन तल बनाने की मांग विधायक राहुल ढिकले ने की। होटल मिर्चीपरिसर में उड्डाण पुल बनाने की मांग भी की गई। यातायात सुचारू करने के लिए द्वारका और मुंबई नाका परिसर में होने वाला टैक्सी स्टैंड और ट्रैवल वाहन तल नदी पात्र के नजदीक स्थलांतरित करने की मांग विधायक देवयानी फरांदे ने की। सरस्वती नाले का पानी द्वारका बायपास मार्ग से गोदावरी में छोड़ने पर सराफ बाजार, कापड बाजार में निर्माण होने वाली बाढ़ स्थिति निर्माण न होने की बात कर निर्माण विभाग ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की गई।

चित्रनगरी प्रकल्प पर मंथन

दादासाहब फालके चित्रनगरी के मुद्दे को लेकर विधायक सीमा हिरे ने निजीकरण का प्रयोग करने की मांग की। तो विधायक फरांदे ने दादासाहब फालके राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह दिल्ली के बजाए नासिक के दादासाहब फालके स्मारक में करने की मांग की। साथ ही इस समारोह के लिए केंद्र सरकार ने निधि ने की मांग की। इसके चलते नासिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इस बारे में सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की जानकारी डॉ. पुलकुंडवार ने दी। विधायक सीमा हिरे ने पेलिकन पार्क का उद्घाटन, संभाजी स्टेडियम का नवीनीकरण और सिडको के 28 हजार मकान फ्री होल्ड करने के बारे में जल्द से जल्द प्रक्रिया कार्यान्वित करने की मांग की। महानगरपालिका की ओर से रिक्त पद के लिए भर्ती करने की मांग फरांदे और ढिकले ने की।

मच्छरों के हमले से कांपा दाऊद इब्राहिम का साथी

बोतल में भरकर पहुंचा कोर्ट, कहा- 'बचा लो'

मुंबई : मुंबई की एक अदालत में अजब-गजब मामला आया। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम की गैंग का साथी गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला कोर्ट में मरे हुए मच्छरों से भरी बोतल लेकर पहुंच गया। उसने कोर्ट में बोतल दिखाते हुए कहा कि जेल के अंदर मच्छरों ने परेशान कर दिया है। इसलिए उसे एक मच्छरदानी दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, एजाज लकड़ावाला को जनवरी, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून व अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। 2020 से ही एजाज नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है।

मच्छरदानी के लिए दायर की थी याचिका

हाल ही में एजाज ने कोर्ट में याचिका दायर कर मच्छरदानी की मांग की थी। उसने कहा था कि जब उसे जेल भेजा गया था तो शुरूआत में मच्छरदानी दी गई थी, लेकिन बाद में उसे ले लिया गया। गुरुवार को कोर्ट में वह मच्छरों से भरी बोतल लेकर पहुंच गया और कहा कि हर रोज कैदियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है।

बता दें, सुरक्षा कारणों से जेल प्रशासन ने एजाज से मच्छरदानी वापस ले ली थी। उसकी याचिका का भी अधिकारियों द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ओडोमोस और अन्य मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें, लकड़ावाला के अलावा, तलोजा जेल के कई कैदियों ने भी इसी तरह के आवेदन दायर किए हैं।

विदेश भेजने के नाम पर 1.10 लाख ठगे मुंबई में होटल में रुकवाया, फर्जी टिकट और वीजा दिया...!

सीकर के रामगढ़ शेखावाटी इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक युवक को उसके दो परिचित लोगों ने ही अपने झांसे में ले लिया और उससे 1.10 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद उससे फर्जी टिकट और वीजा भी दिया। दोनों ने उसे मुंबई के एक होटल में भी रुकवाया। साथ ही एक ऑफिस में भी लेकर गए। जहां उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी इलाके के रहने वाले मेनूदीन ने रिपोर्ट देकर बताया है कि उसके घर पर चूरू निवासी अरशद खान और कयूम आए। जिन्होंने उसे विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही पूर्णविराम बदले में दोनों ने 1.10 लाख रुपए मांगे। 17 जून 2022 को मेनूदीन ने दोनों को रुपए दे दिए। इसके बाद 20 जून 2022 को अरशद और उसके साथी ने 20 जून को फर्जी टिकट और वीजा देकर मेनूदीन को मुंबई के भिंडी बाजार में ठहरा दिया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद मेनूदीन को दूसरी टिकट बनवा कर दी और उसी मुंबई के एक ऑफिस में ले गए। मेनूदीन से ऑफिस वाले ने 3 लाख रुपए मांगे। मेनूदीन ने अरशद को फोन किया लेकिन अरशद ने फोन नहीं उठाया। और अब पासपोर्ट देने से भी मना कर रहा है। फिलहाल रामगढ़ शेखावाटी पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

यूपी में शराब के शौकीनों को मिलेगी सहूलियत, दुकानदारों की बढ़ेगी परेशानी...!

यूपी : यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। हालांकि इसमें शराब विक्रेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल ग्राहकों को सही गुणवत्ता, सही मात्रा और सही दाम पर शराब तथा बीयर उपलब्ध करवाने के आबकारी महकमे के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। तमिलनाडु की एक फर्म से हुए करार के बाद शराब व बीयर की फुटकर दुकानों पर लगी प्वांइट आफ सेल यानि पीओएस मशीनें सही ढंग से काम ही नहीं कर रहीं। फुटकर विक्रेताओं की शिकायत है कि यह मशीनें हैंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से शाम को

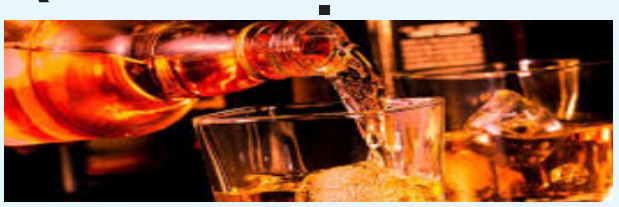

और रात में जब बिक्री बढ़ी हुई होती है, काउंटर पर ग्राहकों की भारी भीड़ होती है उस वक्त इन मशीनों से शराब की बोतल या बीयर के केन स्कैन कर ग्राहकों को उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं हो पाता।

अक्सर इस मुद्दे को लेकर विवाद की नौबत बनती है। शराब व बीयर के फुटकर विक्रेताओं के प्रतिनिधि देवेश जायसवाल का कहना है कि दुकानों पर ग्राहकों की सुविधा के नाम पर यह पीओएस मशीनें लगा तो दी गईं, मगर इनसे न विभाग का भला हो पा रहा और न ग्राहक का, विक्रेताओं और उनके स्टाफ की दिक्कत बढ़ गई सो अलग। ग्राहकों को सही गुणवत्ता, सही मात्रा और सही दाम पर शराब तथा बीयर उपलब्ध करवाने के आबकारी महकमे के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। तमिलनाडु की एक फर्म से हुए करार के बाद शराब व बीयर की फुटकर दुकानों पर लगी प्वांइट आफ सेल यानि पीओएस मशीनें सही ढंग से काम ही नहीं कर रहीं। फुटकर विक्रेताओं की शिकायत है कि यह मशीनें हैंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से शाम को और रात में जब बिक्री बढ़ी हुई होती है, काउंटर पर ग्राहकों की भारी भीड़ होती है उस वक्त इन मशीनों से शराब की बोतल या बीयर के केन स्कैन कर ग्राहकों को उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं हो पाता।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : शनिवार, 05 नवंबर 2022

सुप्रीम कोर्ट का जेनेटिक मोडिफाइड सरसों की खेती पर रोक...!

मुंबई : बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार है और यह इंसान के स्वास्थ्य को खासा प्रभावित करता है। डॉक्टरों का कहना है कि आज लोगों में बढ़ती बीमारी इसकी एक प्रमुख वजह है। फसलों में अत्यधिक कीटनाशक और खाद के प्रयोग ने इस संकट को काफी बढ़ा दिया है।ऐसे में केंद्र सरकार ने आनुवंशिक संशोधित (जेनेटिक मोडिफाइड) सरसों की खेती को अनुमति देकर मानो इस खतरे को और बढ़ा दिया है।इस जीएम सरसों का देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को चटका देते हुए इस जेनेटिकली मोडिफाइड 'जीएम सरसों' की खेती पर रोक लगा दी है।

बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे चुकी है। इस मंजूरी को लेकर कई किसान संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कमेटी के इस पैंतरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत २०१२ में स्थापित टेक कमेटी ने विशेष रूप से जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इस तरह की फसलें जैव सुरक्षा और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। याचिकाकताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के बायोटेक नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अक्टूबर में जीएम सरसों की फसल को मंजूरी दे दी है। इससे देश की जैव विविधता को गंभीर नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलीसिटर जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो मंजूरी और प्रक्रिया से 'संबंधित दस्तावेज' कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। जज दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया की अदालत ने केंद्र से इस हाईब्रिड फसल की खेती को पूरी तरह से मंजूरी देने से फिलहाल रोकने को कहा है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट १० नवंबर को सुनवाई करेगा। कई किसान संगठनों का कहना है कि जीएम सरसों के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा शहद उत्पादन का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो जाएगा।

मोरबी पुल हादसे मामले में सरकार का बड़ा फैसला, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी हुए निलंबित

गुजरात : गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीपसिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है. बता दें, 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी जिसमें हादसे में मरने वालों की वर्तमान संख्या 135 है. ये घटना उस वक्त हुई थी जब लोग अपनी छुट्टियां मनाने और मौज मस्ती के लिए पुल पर आये थे. मोरबी पुल हादसे का वीडियो सामने आने के बाद उसमें देखा गया था कि कुछ लोग पुल पर सबार थे और देखते-देखते ही पुल टूट जाता है और लोग नीचे नदी में गिर जाते हैं. इस नदी में डूबने से 135 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे.

मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साधा निशाना

मुंबई : लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करनेवाले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जमकर निशाना साधा है। लोकतंत्र व संविधान को न माननेवाली भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को एचएमवी ऐसा संबोधित करके गुलामी की उपमा देने का घृणित काम किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री की ओर से ऐसी बात दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा और देवेंद्र फडणवीस इसके लिए माफी मांगें। यह मांग नाना पटोले ने की है। इस संबंध में बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि २०१४ से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से सभी संस्थानों की स्वतंत्रता छीन ली गई है। सरकार के इशारे पर उन्हें नचाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रहरी के रूप में कार्य करता है। वे समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की आलोचना की, सरकार से जवाब मांगा तो मीडिया ने क्या गलत किया? लेकिन जब सत्ता की मस्ती चढ़ती है तो आलोचना बर्दाश्त नहीं होती इसलिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों को एचएमवी और उसी पार्टी के विधायक पराग शाह ने चाय-बिस्कुट बताकर उनका अपमान किया है। यह सत्ता की मस्ती चढ़ने की बात है, ऐसा पटोले ने कहा।

के ई एम का नर्सेस हॉस्टेल का स्लैब गिरा

एक महिला हुई घायल, नर्सेस विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थान पर हटाया जाएगा

मुंबई : मुंबई के ई एम अस्पताल के नर्सेस हॉस्टल में गुरुवार की सुबह लगभग 9 बजकर 30 मिनट पर इमारत का स्लैब गिर गया। इस दुर्घटना में नर्स की पढ़ाई कर रही लड़कियों का खाना बनाने वाली एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। नर्सेस हॉस्टल की अवस्था विकट होने के कारण नर्स की पढ़ाई कर रही लड़कियों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा। स्लैब गिरने की घटना से नर्स की पढ़ाई कर रही लड़कियों और के ई एम में कार्यरत नर्स में गबराहट का माहौल बन गया था। बता दे की के ई एम अस्पताल के पीछे 300 नर्स का हॉस्टल बना हुआ है।यह हॉस्टल इमारत 1926 में बनी हुई है। लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी इमारत की अवस्था विकट बनी हुई है। नर्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का कहना है कि स्लैब गिरने की यह कोई नई घटना नही है।अपनी जान हथेली पर रखकर वह अपनी पढ़ाई कर रही है।स्लैब के साथ साथ कई बार ऊपर लटके पंखे तक गिरे है। लेकिन सुदैव से कोई दुर्घटना नही घटी। गुरुवार को स्लैब गिरने की घटना में लड़कियों का खाना बनाने वाली महिला संगीता चव्हाण 40 साल गंभीर जख्मी हुई है उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। ईलाज के लिए के ई एम अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।इमारत में स्लैब गिरने की घटना के बाद स्थानीय पूर्व नगरसेवक अनिल कोकिल घटना स्थल का दौरा किया।इमारत की खस्ता हाल देखकर पढ़ने वाली लड़कियों को दूसरे स्थान पर हटाने की मांग केईएम की प्रभारी डीन डॉ पाठक ने कहा की लड़कियों को रहने की दूसरी व्यवस्था की जा रही है।

इस हॉस्टल की इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था जिसमे इमारत को सी 2 घोषित किया गया है जिसके अनुसार इमारत की मरम्मत करना अतियावशायक है।इमारत का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।इस तरह की जानकारी अस्पताल की प्रभारी डीन डॉ पाठक ने दी।उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर स्लैब गिरा है इस परिसर का तत्काल मरम्मत कार्य किया जाएगा।

३१.७४ फीसदी मतदान, रविवार को आएगा नतीजा

मुंबई : अंधेरी निर्वाचन क्षेत्र में कल हुए उपचुनाव में सुबह ७ से शाम ६ बजे तक कुल ३१.७४ फीसदी मतदान हुआ। इस उपचुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्ष की तरफ से महाविकास आघाड़ी की ऋतुजा लटके मैदान में हैं, ऋतुजा लटके को महाविकास आघाड़ी का भारी समर्थन मिला है। दूसरी तरफ कमजोर विरोधियों के चलते शिवसेना ही मैदान मारेगी अर्थात जीत निश्चित मानी जा रही है। रविवार को इस चुनाव का परिणाम घोषित होगा।

शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के चलते यह उपचुनाव हो रहा है। यह भले ही उपचुनाव था लेकिन सुबह ७ बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा था। कई मतदान केंद्रों पर युवकों के साथ ही ८० साल से अधिक आयु के वृद्ध भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। मतदाताओं के इसी उत्साह के चलते सुबह ११ बजे तक १० फीसदी मतदान हुआ। उपचुनाव के लिए ३८ विभिन्न क्षेत्रों में २५६ मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्रों पर १०० मीटर क्षेत्र में मतदाताओं के अलावा नागरिकों और मीडिया के प्रवेश को वर्जित किया गया था। वहीं दोपहर के बाद मतदान ने फिर से रफ्तार पकड़ी। दोपहर एक बजे तक मतदान का यह आंकड़ा १७ फीसदी तक पहुंच गया। वहीं दोपहर के बाद मतदान का जोर और बढ़ने लगा और शाम ६ बजे तक कुल ३१.७४ फीसदी मतदान हुआ। बताया गया है कि वोटों की गिनती गुंदवली म्युनिसिपल स्कूल भीम नगर, अंधेरी (पूर्व) में रविवार ६ नवंबर को सुबह ७ बजे से शुरू हो जाएगी। अंधेरी (पूर्व) उपचुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की ऋतुजा लटके के साथ आपकी अपनी पार्टी-पीपुल्स पार्टी से बाला नाडार, राइट टू रिकॉल पार्टी से मनोज नायक, जबकि निर्दलीय नीना खेडेकर, फरहाना सैयद, मिलिंद कांबले, राजेश त्रिपाठी मैदान में हैं। इन सभी का भविष्य कल मत पेटी में बंद हो गया।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com